

हीराचंद श्रीनिवास मनगांवकर

बनाम

सुनंदा

20 मार्च, 2001

[डी. पी. मोहपात्रा और दोराईस्वामी राजू, जे. जे.]

हिंदू कानून:

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: धारा 10 (2), 13 (1-ए) (आई) और 23 {1} (ए)।

न्यायिक पृथक्करण-भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया गया-तलाक याचिका-भरण-पोषण-पति के व्यभिचार के आधार पर पत्नी के आवेदन पर पारित न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री-पति ने पत्नी और बेटी को भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया-पति व्यभिचार में रहता रहा-पति ने तलाक के लिए याचिका दायर की क्योंकि सहवास एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए फिर से शुरू नहीं हुआ था। केवल इसलिए कि अपेक्षित अवधि के लिए कोई सहवास नहीं है, तलाक की डिक्री देना अनिवार्य नहीं है-न्यायिक पृथक्करण के बाद दोनों पति-पत्नियों का कर्तव्य है कि वे सहवास के लिए अपने हिस्से का पालन करें-पति अपनी पत्नी और बेटी को भरण-पोषण देने से इनकार करने में और व्यभिचार में रहने के अर्थ के भीतर एक 'दोष' किया। 23 (1) (ए)-इसलिए, उच्च न्यायालय ने तलाक की डिक्री देने से इनकार कर दिया।

शब्द और वाक्यांश:

"दोष"-का अर्थ-हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 (1) (ए) के संदर्भ में।

प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलार्थी-पति की ओर से व्यभिचार के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने न्यायिक पृथक्करण के लिए एक आदेश पारित किया और अपीलकर्ता को प्रतिवादी और उसकी बेटी को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, अपीलकर्ता ने इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की कि न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित करने के बाद एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षों के बीच सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता भरण-पोषण के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं करके अपनी गलती का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए यह अपील की गई है।

प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बाद भी अपीलकर्ता व्यभिचार में रह रहा था और इसलिए, तलाक के लिए अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठे:

1. क्या वह पति जिसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की खंड 13 (1-ए) के तहत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने की याचिका दायर की थी, उसे इस आधार पर राहत देने से इनकार किया जा सकता है कि वह अदालत के आदेश के बावजूद अपनी पत्नी और बेटी को भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहा था?

2. क्या खंड 13 (1-ए) के तहत दायर तलाक के लिए याचिका में, अदालत के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की खंड 23 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर डिक्री पारित करने से इनकार करने के लिए खुला था, जहां तक उनमें से कोई एक या अधिक लागू हो सकता है?

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की खंड 13 (1-ए) विवाह के लिए किसी भी पक्ष को अधिकार प्रदान करती है ताकि तलाक के लिए याचिका न केवल उस पक्ष द्वारा दायर की जा सके जिसने न्यायिक पृथक्करण या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की थी, बल्कि उस पक्ष के लिए भी जिसके खिलाफ ऐसी डिक्री पारित की गई थी। उप-धारा (1-ए) का उद्देश्य केवल तलाक के लिए आवेदन करने के अधिकार का विस्तार करना है और यह बाध्यकारी नहीं बनाना है कि उप-धारा (1-ए) के तहत प्रस्तुत तलाक के लिए याचिका को केवल इस प्रमाण पर अनुमति दी जानी चाहिए कि अपेक्षित अवधि के लिए कोई सहवास या क्षतिपूर्ति नहीं थी। खंड 23 की भाषा से ही पता चलता है कि यह अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यवाही को नियंत्रित करती है और न्यायालय पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह मांगी गई राहत का आदेश केवल तभी जारी करे जब उप-खंड में उल्लिखित शर्तें संतुष्ट हों, और अन्यथा नहीं। [499-बी-ई]

2. न्यायिक पृथक्करण का फरमान पारित होने के बाद, पत्नी द्वारा दायर याचिका पर, दोनों पति-पत्नियों का कर्तव्य था कि वे सहवास के लिए अपनी भूमिका निभाएं। पति से अपेक्षा की जाती थी कि वह पत्नी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ पति के रूप में कार्य करे और पत्नी से पति के प्रति समर्पित पत्नी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने से इनकार करने में पति पति के रूप में कार्य करने में विफल रहा। इस प्रकार उन्होंने अधिनियम की खंड 23 के अर्थ के भीतर एक 'गलत' किया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की खंड 13 (1-ए) के तहत तलाक द्वारा विवाह को भंग करने के लिए पति की प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। [500-बी-डी]

3.1, अधिनियम की खंड 13 (1-ए) केवल विवाह के किसी भी पक्ष को उसमें

बताए गए किसी भी आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए आवेदन दायर करने में सक्षम बनाती है। इस खंड में यह प्रावधान नहीं है कि एक बार जब आवेदक उसमें निर्दिष्ट शर्तों में से एक को पूरा करने का आरोप लगाते हुए आवेदन करता है तो अदालत के पास तलाक की डिक्री देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। खंड की ऐसी व्याख्या अधिनियम की खंड 23 (1) (ए) के प्रावधानों के विपरीत होगी। [500-जी-एच; 501-ए]

3.2. यदि खंड 13 (1-ए) और खंड 23 (1) (ए) के प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाता है, तो जो स्थिति सामने आती है, वह यह है कि याचिकाकर्ता को दूसरे पक्ष के खिलाफ तलाक की डिक्री से राहत पाने का निहित अधिकार नहीं है, केवल यह दिखाने पर कि याचिका में बताई गई राहत के समर्थन में आधार मौजूद है। [501-सी]

धर्मेंद्र कुमार बनाम उषा कुमार, [1977] 4 एस. सी. सी. 12, लागू नहीं था।

मुल्ला का हिंदू कानून 17 वीं संस्करण पी 121, संदर्भित किया गया।

4.1. अधिनियम की खंड 10 (2) को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान उस याचिकाकर्ता पर लागू होता है जिसके आवेदन पर न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित की गई है। यह मानते हुए भी कि यह प्रावधान याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी दोनों के लिए है, यह याचिकाकर्ता या प्रतिवादी को न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित होने के बाद दूसरे पक्ष के साथ सहवास का प्रयास नहीं करने का कोई आत्यन्तिक अधिकार नहीं देता है। जैसा कि प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री इस अर्थ में अंतिम नहीं है कि यह अपरिवर्तनीय है; अदालत में डिक्री को रद्द करने की शक्ति निहित है यदि वह किसी भी पक्ष के आवेदन पर ऐसा करना उचित और उचित समझती है। डिक्री का प्रभाव यह है कि विवाह से उत्पन्न होने वाले कुछ पारस्परिक अधिकार और दायित्व निलंबित किए

गए हैं और डिक्री में निर्धारित अधिकारों और कर्तव्यों को इसके लिए प्रतिस्थापित किया गया है। न्यायिक पृथक्करण का फरमान विवाह बंधन को तोड़ता या भंग नहीं करता है, जो अभी भी बना हुआ है। यह जीवनसाथी को सुलह और पुनः समायोजन का अवसर प्रदान करता है। डिक्री पक्षों के सुलह द्वारा गिर सकती है, जिस स्थिति में संबंधित पक्षों के अधिकार, जो विवाह से तैरते हैं और निलंबित किए गए थे, बहाल किए जाते हैं। इसलिए, यह धारणा कि खंड 10 (2) याचिकाकर्ता को तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार देती है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने प्रतिवादी के साथ सहवास का कोई प्रयास नहीं किया है और यहां तक कि सहवास के लिए किसी भी कदम को विफल करने के तरीके से काम किया है, वैधानिक प्रावधानों की उचित व्याख्या से नहीं निकलती है। यह कहा जा सकता है कि अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध बनाए रखना है और इस तरह के संबंध को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है। [502-डी-एच; 503-ए]

4.2, वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी न केवल ऐसा कोई प्रयास करने में विफल रहा है, बल्कि उसने पत्नी के लिए भरण-पोषण का भुगतान करने से भी इनकार कर दिया है और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बाद एक साल की वैधानिक अवधि की समाप्ति के लिए समय निर्धारित कर रहा है ताकि वह आसानी से तलाक की डिक्री प्राप्त कर सके। इन परिस्थितियों में यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि वह न केवल अपनी पत्नी का पालन-पोषण करने से इनकार करने में वैवाहिक गलती करता है और किसी भी पुनः नियुक्ति को असंभव बनाते हुए कटुता पैदा करने वाले संबंध को और तोड़ देता है, बल्कि तलाक की राहत पाने के लिए उक्त 'गलत' का लाभ उठाने की भी कोशिश करता है। चूक करने में इस तरह के आचरण को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि खंड 13 (1-ए) के तहत तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए उसे अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त महत्व का मामला नहीं है। [503-सी-ई]

5, इस मामले में पति की ओर से व्यभिचार में रहना एक निरंतर वैवाहिक अपराध है। अपराध केवल न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिक्री के पारित होने पर रोक या मिटा नहीं जाता है, जो केवल उनके विवाह के संबंध में पति या पत्नी के कुछ कर्तव्यों और दायित्वों को निलंबित करता है और वैवाहिक संबंध को नहीं तोड़ता है।  
[504-एफ-जी]

सौंदरम्मल बनाम सुंदरा महालिंगा नादर, (1980) मैड। 294, स्वीकृत।

सुमित्र मन्ना बनाम गोबिंद चंद्र मन्ना, आकाशवाणी (1988) कैल। 192 और बाल मणि बनाम जयंतीलाल दहियाभाई, ए. टी. आर. (1979) गुजरात। 209, खारिज कर दिया।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल याचिका सं 1473/1999

उच्च न्यायालय कर्नाटक 1988 के एम. एफ. ए. सं. 1436 के निर्णय और आदेश दिनांक 10.4.95 से।

अपीलकर्ता की ओर से सुश्री किरण सूरी।

के. आर. नागराजा, के. के. त्यागी, ए. पी. प्रत्यर्थी के लिए जैन और एम. शारदा।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी. पी. मोहपात्रा, जे.

इस मामले में निर्धारण के लिए जो बिन्दु उत्पन्न है, वह संक्षिप्त है लेकिन किसी भी तरह से सरल नहीं है। मुद्दा यह है: क्या वह पति जिसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') की खंड 13 (1-ए) (1) के तहत तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने की याचिका दायर की है, उसे इस आधार पर राहत देने

से इनकार किया जा सकता है कि वह अदालत के आदेश के बावजूद अपनी पत्नी और बेटी को भरण-पोषण का भुगतान करने में विफल रहा है?

प्रश्न के निर्धारण के लिए आवश्यक मामले के प्रासंगिक तथ्यों को इस प्रकार कहा जा सकता है:

अपीलकर्ता प्रत्यर्थी का पति होता है। प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर-अधिनियम की खंड 10 के तहत अपीलकर्ता की ओर से व्यभिचार के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 6.1.1981 पर न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिक्री पारित की गई थी। उक्त आदेश में अदालत ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए आदेश दिया कि अपीलकर्ता पत्नी को प्रति माह भरण-पोषण के रूप में Rs.100 और बेटी के लिए प्रति माह Rs.75 का भुगतान करेगा। तब से अपीलकर्ता द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया है और प्रतिवादी को भरण-पोषण के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद, आई. डी. 1 पर अपीलकर्ता ने इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की कि न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित करने के बाद एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षों के बीच सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ है।

प्रत्यर्थी ने इस आधार पर तलाक के लिए याचिका का विरोध किया कि अपीलकर्ता अदालत के आदेश के अनुसार भरण-पोषण का भुगतान करने अन्य बातों के साथ साथ विफल रहने के कारण उसके द्वारा दायर तलाक की याचिका खारिज होने योग्य है क्योंकि वह राहत पाने के लिए अपनी गलती का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। उच्च न्यायालय ने M.F.A.No 1436/1988 में दिनांकित 10.4.1995 निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई प्ली को स्वीकार कर लिया और तलाक के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उक्त आदेश अपीलकर्ता

द्वारा इस अपील में लागू किया जाता है।

पहले तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर खंड 13 (1-ए) की व्याख्या और अधिनियम की खंड आई. ओ. और 23 (एल) (ए) के साथ इसकी बातचीत पर निर्भर करता है।

अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री किरण सूरी ने तर्क दिया कि खंड 13 (1-ए) के तहत तलाक लेने की एकमात्र शर्त यह है कि न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षों के बीच सह-निवास फिर से शुरू नहीं हुआ है, जिसमें दोनों पति-पत्नी पक्षकार थे। यदि यह पूर्व शर्त पूरी हो जाती है, तो सुश्री सूरी ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय को तलाक की डिक्री पारित करनी है। श्री सूरी के अनुसार खंड 23 (1) (ए) का खंड 13 (1-ए) (आई) के तहत किसी मामले में कोई आवेदन नहीं है। वैकल्पिक रूप से, उसने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए 'गलत' का कार्यवाही में मांगी गई राहत यानी तलाक की डिक्री पारित करने से कोई संबंध नहीं है। श्री सूरी के अनुसार भरण-पोषण के भुगतान के लिए एक आदेश एक निष्पादन योग्य आदेश है और यह प्रतिवादी के लिए कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करके देय राशि का भुगतान करने के लिए खुला है।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिकॉर्ड से उपलब्ध मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने तलाक की डिक्री के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को इस आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया कि यह कदम प्रामाणिक नहीं था, कि वह न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद भी व्यभिचार में रहता है और वह अपनी पत्नी और बेटी को बनाए रखने में विफल रहा है। श्री नागराजा ने प्रस्तुत किया कि तलाक की डिक्री के लिए उनकी प्रार्थना को मंजूरी देना प्रत्यर्थी और उसके बच्चे के प्रति अपीलकर्ता द्वारा किए गए गलत पर एक



प्रीमियम डालना होगा।श्री नागराजा ने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को अपनी पत्नी और बेटी (Rs.100 + Rs.75 प्रति माह) को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देते हुए प्रत्यर्थी द्वारा बेटी के शिक्षा खर्च और शादी के खर्च के लिए की गई प्रार्थना पर कोई आदेश पारित नहीं किया।

चूँकि मामले का निर्णय खंड 13 (1-ए) (आई) के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अधिनियम की खंड 10 और 23 (1) (ए) के साथ इसकी बातचीत पर निर्भर करता है, इसलिए दोनों खंडों के प्रासंगिक भागों को यहाँ उद्धृत किया गया है:

"13. तलाक-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह, पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है कि दूसरा पक्ष -

((i) विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाए हों, या

((क) विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है; या

((ख) याचिकाकर्ता को याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए छोड़ दिया है; या

XXXXXXXX

(1-क) विवाह का कोई भी पक्ष, जब भी इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न होता है, तो इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए याचिका भी प्रस्तुत कर सकता है -

((i) यह कि जिस कार्यवाही में वे पक्षकार थे, उस कार्यवाही में

न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षों के बीच सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ है; या

(ख) विवाह के पक्षकारों के बीच वैवाहिक अधिकारों की किसी कार्यवाही में, जिसमें वे पक्षकार थे, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कोई पुनर्स्थापना नहीं हुई है।”

खंड 10 इस प्रकार प्रदान करती है:

“10. न्यायिक पृथक्करण-(1) विवाह का कोई भी पक्ष, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न हो, खंड 13 की उप-खंड (1) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री का अनुरोध करते हुए एक याचिका प्रस्तुत कर सकता है, और एक पत्नी के मामले में भी उप-खंड (2) में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर, जिसके आधार पर तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत की गई होगी।

(2) जहां न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित की गई है, वहां याचिकाकर्ता के लिए अब प्रतिवादी के साथ रहना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन अदालत, किसी भी पक्ष की याचिका द्वारा आवेदन पर और ऐसी याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर, डिक्री को रद्द कर सकती है यदि वह ऐसा करना उचित और उचित समझती है।”

खंड 23 (1) (ए) निम्नलिखित प्रावधान करती है:

(क) राहत देने के लिए कोई भी आधार मौजूद है और याचिकाकर्ता

उन मामलों को छोड़कर जहां खंड 5 के खंड (ii) के उपखंड (क), उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट आधार पर राहत मांगी गई है, किसी भी तरह से ऐसी राहत के उद्देश्य से अपनी गलती या अक्षमता का लाभ नहीं उठा रहा है।”

मूल रूप से खंड 13 की उप-खंड (1) के तहत तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए पति या पत्नी के लिए नौ अलग-अलग आधार उपलब्ध थे। उप-धारा के खंड (viii) के तहत पति या पत्नी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को इस आधार पर भंग किया जा सकता है कि दूसरे पक्ष ने उस पक्ष के खिलाफ न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित करने के बाद दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए सहवास फिर से शुरू नहीं किया है। उप-खंड के खंड (ix) के तहत, पति या पत्नी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को इस आधार पर भंग किया जा सकता है कि दूसरा पक्ष उस पक्ष के खिलाफ क्षतिपूर्ति की डिक्री पारित करने के बाद दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री का पालन करने में विफल रहा है।

1964 के संशोधन अधिनियम, जो 20 दिसंबर, 1964 को लागू हुआ, ने दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। खंड (viii) और (ix) जो उन नौ आधारों में से दो थे जिन पर विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता था, उन्हें उप-खंड (1) से हटा दिया गया और दूसरा, खंड 13 में एक नई उप-खंड यानी उप-खंड (1-ए) को जोड़ा गया। 1964 के अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किए गए इन संशोधनों से यह स्पष्ट है कि जबकि संशोधन से पहले तलाक के लिए याचिका केवल उस पक्ष द्वारा दायर की जा सकती थी जिसने न्यायिक पृथक्करण या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की थी, यह अधिकार अब विवाह के लिए किसी भी पक्ष को उपलब्ध है, भले ही तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत करने वाला पक्ष न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री या

वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के तहत डिक्री धारक हो या निर्णय ऋणी हो, जैसा भी मामला हो। यह स्थिति निर्विवाद है।

सवाल यह है: चाहे खंड 13 की उप-खंड (1-ए) के तहत दायर तलाक के लिए याचिका में, न्यायालय अधिनियम की खंड 23 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर डिक्री पारित करने से इनकार करने के लिए खुला है, जहां तक उनमें से कोई एक या अधिक लागू हो सकता है।

यह तर्क कि खंड 13 की उप-खंड (1-ए) द्वारा प्रदत्त अधिकार आत्यन्तिक और अयोग्य है और यह नया प्रदत्त अधिकार खंड 23 के प्रावधानों के अधीन नहीं है, गलत है। यह तर्क इस गलत धारणा पर आधारित प्रतीत होता है कि खंड 13 की उप-खंड (1-ए) के तहत दायर याचिका के निर्धारण में खंड 23 (1) के तहत उत्पन्न होने वाले विचार को लागू करना 1964 के संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को पूरी तरह से अर्थहीन बनाना है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, खंड 13 (1) के खंड (viii) और (ix) के तहत संशोधन से पहले तलाक के लिए आवेदन करने का अधिकार उस पक्षकार तक सीमित था जिसने न्यायिक पृथक्करण या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की थी। ऐसा अधिकार उस पक्ष के लिए उपलब्ध नहीं था जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई थी। खंड 13 की उप-खंड (1-ए), जिसे संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, विवाह के लिए किसी भी पक्ष को ऐसा अधिकार प्रदान करती है ताकि संशोधन के बाद तलाक के लिए याचिका न केवल उस पक्ष द्वारा दायर की जा सके जिसने न्यायिक पृथक्करण या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त की थी, बल्कि उस पक्ष के लिए भी जिसके खिलाफ ऐसी डिक्री पारित की गई थी। यह 1964 के अधिनियम No.44 द्वारा पेश किए गए संशोधन का सीमित उद्देश्य और प्रभाव है। संशोधन इस आदेश में पेश नहीं किया गया था कि खंड 23 में निहित प्रावधानों को निरस्त किया जाए और यह भी संशोधन का प्रभाव नहीं है। उप-धारा (1-ए) का उद्देश्य

केवल तलाक के लिए आवेदन करने के अधिकार का विस्तार करना था और यह बाध्यकारी नहीं बनाना था कि उप-धारा (1-ए) के तहत प्रस्तुत तलाक के लिए याचिका को केवल इस प्रमाण पर अनुमति दी जानी चाहिए कि अपेक्षित अवधि के लिए कोई सहवास या क्षतिपूर्ति नहीं थी। खंड 23 की भाषा से ही पता चलता है कि यह अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यवाही को नियंत्रित करती है और न्यायालय पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह मांगी गई राहत का आदेश केवल तभी जारी करे जब उप-खंड में उल्लिखित शर्तें संतुष्ट हों, और अन्यथा नहीं। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क कि खंड 23 (1) के प्रावधान अधिनियम की खंड 13 की उप-खंड (1-ए) के तहत दायर याचिका पर निर्णय लेने में प्रासंगिक नहीं हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अगला विवाद जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता ने पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने से इनकार करके खंड 23 के अर्थ के भीतर 'गलत' किया है और क्या तलाक की राहत लेने में वह अपने 'गलत' का लाभ उठा रहा है। मुल्ला के हिंदू कानून (पृष्ठ 121 पर 17वां संस्करण) में कहा गया है: "सहवास का अर्थ है पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहना। इसमें पति पत्नी के प्रति पति के रूप में कार्य करता है और पत्नी पति के प्रति पत्नी के रूप में कार्य करती है, पत्नी पति के प्रति गृहिणी कर्तव्यों को निभाती है और पति को पति के रूप में अपनी पत्नी का समर्थन करना चाहिए। सहवास आवश्यक रूप से इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध है या नहीं। यदि संभोग है, तो यह बहुत मजबूत सबूत है-यह निर्णायक सबूत हो सकता है-कि वे सहवास कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्योंकि वे संभोग नहीं करते हैं वे सहवास नहीं कर रहे हैं। सहवास का तात्पर्य केवल निवास से कुछ अलग है। इसका मतलब यह होना चाहिए कि पति और पत्नी ने इस तरह से काम करना शुरू कर दिया है और पति और पत्नी के रूप में अपनी स्थिति को फिर से शुरू कर दिया है।" (जोर दिया गया)

पत्नी द्वारा दायर याचिका पर न्यायिक पृथक्करण का आदेश पारित होने के बाद दोनों पति-पत्नियों का कर्तव्य था कि वे सहवास के लिए अपनी भूमिका निभाएं। पति से अपेक्षा की जाती थी कि वह पत्नी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ पति के रूप में कार्य करे और पत्नी से पति के प्रति समर्पित पत्नी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। यदि न्यायिक पृथक्करण के बाद सफल सहवास के उद्देश्य से दोनों पति-पत्नियों के ईमानदारी से योगदान करने की इस अवधारणा का आदेश दिया जाता है, तो यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पति पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार करने में विफल रहा। इस प्रकार उन्होंने अधिनियम की खंड 23 के अर्थ के भीतर एक 'गलत' किया। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की खंड 13 (1-ए) के तहत तलाक द्वारा विवाह को भंग करने के लिए पति की प्रार्थना को अनुमति देने से इनकार कर दिया।

इस संबंध में इस स्थिति के बारे में एक धारणा को स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि एक बार अधिनियम की खंड 13 (1-ए) के तहत तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए वाद हेतुक उत्पन्न होने पर तलाक प्राप्त करने का अधिकार स्पष्ट हो जाता है और अदालत को आवेदक द्वारा मांगी गई तलाक की राहत देनी होती है। यह धारणा खंड 13 (1-ए) में प्रावधान की गलत व्याख्या पर आधारित है। उक्त खंड में केवल इतना ही उपबंध किया गया है कि विवाह का कोई भी पक्ष इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि उस कार्यवाही में जिसमें वे पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षकारों के बीच सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ है या उस कार्यवाही में जिसमें दोनों पति-पत्नी पक्षकार थे, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षकारों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। यह

खंड निष्पक्ष रूप से पढ़ी जाती है, केवल विवाह के किसी भी पक्ष को उसमें बताए गए किसी भी आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए आवेदन दायर करने में सक्षम बनाती है। इस खंड में यह प्रावधान नहीं है कि एक बार जब आवेदक उसमें निर्दिष्ट शर्तों में से एक को पूरा करने का आरोप लगाते हुए आवेदन करता है तो न्यायालय के पास तलाक की डिक्री देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। खंड की ऐसी व्याख्या अधिनियम की खंड 23 (1) (ए) या (बी) के प्रावधानों के विपरीत होगी। खंड 23 (1) में यह निर्धारित किया गया है कि यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि राहत देने के लिए कोई भी आधार मौजूद है और इसके अलावा कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से ऐसी राहत के उद्देश्य से अपनी 'गलती' या अक्षमता का लाभ नहीं उठा रहा है और खंड (बी) में न्यायालय को यह संतुष्ट करने का आदेश दिया गया है कि खंड 13 की उप-खंड (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आधार पर आधारित याचिका के मामले में, याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से शिकायत किए गए कार्य या कार्यों के लिए सहायक या मिलीभगत या माफी नहीं दी है, या जहां याचिका का आधार क्रूरता है, तो याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से क्रूरता को माफ नहीं किया है और (बीबी) में जब तलाक की मांग की जाती है। यदि खंड 13 (1ए) और खंड 23 (1) (ए) के प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाता है तो जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि याचिकाकर्ता को दूसरे पक्ष के खिलाफ तलाक की डिक्री से राहत पाने का निहित अधिकार नहीं है, केवल यह दिखाने पर कि याचिका में बताई गई राहत के समर्थन में आधार मौजूद है। यह ध्यान में रखना होगा कि पति-पत्नी के बीच संबंध मानव जीवन को प्रभावित करने वाला मामला है। मानव जीवन बिंदीदार रेखाओं या अधिनियम द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर नहीं चलता है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि विवाह के पक्षों के बीच संबंधों को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने से पहले रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए जो न

केवल व्यक्तियों या उनके बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन की राहत दी जानी है या नहीं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे मामले में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का एक सामान्य सिद्धांत निर्धारित करना बहुत खतरनाक होगा।

इस संबंध में धर्मेन्द्र कुमार बनाम उषा कुमार, [1977] 4 एस. सी. सी. 12 के मामले में इस न्यायालय के फैसले का अक्सर उल्लेख किया जाता है। इसमें इस न्यायालय ने इस तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान देते हुए कि लिखित बयान में केवल यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अपीलकर्ता द्वारा लिखे गए कुछ पत्रों को प्राप्त करने से इनकार कर दिया और उसे उसके साथ जीवित रखने के उसके अन्य प्रयासों का जवाब नहीं दिया, यह अभिनिर्धारित किया कि आरोप भले ही सच हों, लेकिन यह दुर्व्यवहार इतना गंभीर नहीं है कि पत्नी को उस राहत के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए जो उसने मांगी है। उस संबंध में इस न्यायालय ने कहा कि खंड 23 (1) के अर्थ के भीतर 'गलत' होने के आदेश कथित आचरण को पुनर्मिलन के प्रस्ताव पर सहमत होने के आदेश केवल अनिच्छा से कुछ अधिक होना चाहिए, यह इतना गंभीर कदाचार होना चाहिए कि उस राहत से इनकार को उचित ठहराया जा सके जिसका पति या पत्नी अन्यथा हकदार है। निर्णय को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि तलाक के लिए आवेदन में याचिकाकर्ता केवल राहत के समर्थन में उसके द्वारा अनुरोध किए गए आधार के अस्तित्व को स्थापित करने पर राहत का हकदार है और न ही यह कि निर्णय इस सिद्धांत को निर्धारित करता है कि अदालत को याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है, जहां उसके द्वारा अनुरोध किए गए आधार की पूर्ति स्थापित हो गई है।

इस संबंध में विचार के लिए एक अन्य प्रश्न अधिनियम की खंड 10 (2) का अर्थ और तात्पर्य है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जहां न्यायिक पृथक्करण के



लिए एक डिक्री पारित की गई है, वहां याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी के साथ रहना अब अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन अदालत, किसी भी पक्ष की याचिका द्वारा आवेदन पर और ऐसी याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर, डिक्री को रद्द कर सकती है यदि वह ऐसा करना उचित समझती है। सवाल यह है कि क्या इस वैधानिक प्रावधान को हाथ में लिए गए मामले में लागू करते हुए यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी के साथ रहने के कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया था क्योंकि न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पर पारित की गई है। उप-धारा (2) के निष्पक्ष अध्ययन पर यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान उस याचिकाकर्ता पर लागू होता है जिसके आवेदन पर न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित की गई है। यह मानते हुए भी कि यह प्रावधान याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी दोनों के लिए है, यह याचिकाकर्ता या प्रतिवादी को न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित होने के बाद दूसरे पक्ष के साथ सहवास का कोई प्रयास नहीं करने का कोई आत्यन्तिक अधिकार नहीं देता है। जैसा कि प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री इस अर्थ में अंतिम नहीं है कि यह अपरिवर्तनीय है; अदालत में डिक्री को रद्द करने की शक्ति निहित है यदि वह किसी भी पक्ष के आवेदन पर ऐसा करना उचित और उचित समझती है। डिक्री का प्रभाव यह है कि विवाह से उत्पन्न होने वाले कुछ पारस्परिक अधिकार और दायित्व निलंबित किए गए हैं और डिक्री में निर्धारित अधिकारों और कर्तव्यों को इसके लिए प्रतिस्थापित किया गया है। न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री विवाह बंधन को अलग या भंग नहीं करती है जो अभी भी बनी हुई है। यह जीवनसाथी को सुलह और पुनः समायोजन का अवसर प्रदान करता है। डिक्री पक्षों के सुलह द्वारा गिर सकती है जिस स्थिति में संबंधित पक्षों के अधिकार जो विवाह से तैरते हैं और निलंबित किए गए थे, उन्हें बहाल किया जाता है। इसलिए यह धारणा कि खंड 10 (2) याचिकाकर्ता को तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार देती

है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने प्रतिवादी के साथ सहवास का कोई प्रयास नहीं किया है और यहां तक कि सहवास के लिए किसी भी कदम को विफल करने के तरीके से काम किया है, वैधानिक प्रावधानों की उचित व्याख्या से नहीं निकलती है। पुनरावृत्ति की कीमत पर यहां यह कहा जा सकता है कि अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध बनाए रखना है न कि ऐसे संबंध को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना।

अब हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जो विशेष रूप से मामले में निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है; क्या अपीलकर्ता द्वारा गुजारा भत्ता देने से इनकार करना अधिनियम की खंड 23 (1) (ए) के अर्थ के भीतर एक 'गलत' है ताकि अपीलकर्ता को तलाक की राहत से वंचित किया जा सके। प्रश्न का उत्तर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इस उद्देश्य के लिए कोई सामान्य सिद्धांत या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि पत्नी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर अदालत द्वारा न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित किए जाने के बाद भी यह उम्मीद की जाती थी कि दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ सुलह और सहवास के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे, जिसका अर्थ है कि पति को कर्तव्यनिष्ठ पति के रूप में व्यवहार करना चाहिए और पत्नी को एक समर्पित पत्नी के रूप में व्यवहार करना चाहिए। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी न केवल ऐसा कोई प्रयास करने में विफल रहा है, बल्कि उसने पत्नी के लिए भरण-पोषण के रूप में Rs.100 की छोटी राशि का भुगतान करने से भी इनकार कर दिया है और न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के बाद एक साल की वैधानिक अवधि की समाप्ति के लिए समय चिह्नित कर रहा है ताकि वह आसानी से तलाक की डिक्री प्राप्त कर सके। इन परिस्थितियों में यह उचित रूप से कहा जा सकता है कि वह न केवल अपनी पत्नी का पालन-पोषण करने से इनकार करने में वैवाहिक गलती करता है और किसी भी पुनः

नियुक्ति को असंभव बनाते हुए कड़वाहट पैदा करने वाले संबंध को और अलग करता है, बल्कि तलाक की राहत पाने के लिए उक्त 'दोष' का लाभ उठाने की भी कोशिश करता है। चूक करने में इस तरह के आचरण को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह खंड 13 (1 ए) के तहत तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए उसे अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त महत्व का मामला नहीं है।

इस संबंध में सुमित्र मन्ना बनाम गोबिंद चंद्र मन्ना, ए. आई. आर. (1988) अनुच्छेद 192 के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को संदर्भित किया जा सकता है जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 या 1973 या 1898 की दंड प्रक्रिया संहिताओं के प्रावधानों के तहत गुजारा भत्ता या भरण-पोषण का आदेश दिया जाता है और पति आदेश का पालन नहीं करता है, तो कुछ परिस्थितियों में वह उस अधिनियम की खंड 13 (2) (iii) के तहत तलाक के लिए डिक्री प्राप्त करने में पत्नी को लाभ दिला सकता है। लेकिन खंड 13 (1 ए) के तहत पत्नी के खिलाफ तलाक के लिए डिक्री प्राप्त करने में पत्नी को कोई गुजारा भत्ता या भरण-पोषण का भुगतान करने में विफलता के लिए पति को कोई लाभ नहीं मिल सकता है या नहीं मिल सकता है और इसलिए, पति को किसी भी तरह से खंड 13 (1 ए) के तहत तलाक के लिए अपनी याचिका पर मुकदमा चलाने में खंड 23 (1) (ए) के अर्थ के भीतर इस तरह के भुगतान का लाभ उठाने में नहीं कहा जा सकता है। यह निर्णय, जो अधिनियम की खंड 23 (1) (ए) में अंतर्निहित प्रशंसनीय उद्देश्य को दरकिनार करते हुए प्रासंगिक प्रावधानों के संकीर्ण निर्माण पर आगे बढ़ता है, हमारे विचार में, कानून की सही स्थिति को निर्धारित नहीं करता है।

जिस प्रश्न पर विचार किया जाना बाकी है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी-पति को व्यभिचार के आधार पर न्यायिक

ए

पृथक्करण के लिए डिक्री पारित करने के बाद भी मालकिन के साथ रहना जारी रखते हुए खंड 23 (1) (ए) के अर्थ के भीतर 'गलत' किया और किया गया कहा जा सकता है। प्रत्यर्थी ने इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की कि अपीलकर्ता व्यभिचार में रह रहा है क्योंकि वह उसके साथ विवाह के दौरान किसी अन्य महिला के साथ रह रहा है। अदालत ने आरोप को स्वीकार कर लिया और न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित की। डिक्री के बाद भी अपीलकर्ता ने स्थिति में कोई बदलाव करने का कोई प्रयास नहीं किया और मालकिन के साथ रहना जारी रखा। बिना किसी पश्चाताप के इस तरह के व्यभिचारी जीवन का पीछा करना, उसके बाद भी, एक और 'गलत' है जिसे उन्होंने जानबूझकर करना जारी रखा, ताकि फिर से एकजुट होने के किसी भी प्रयास को विफल किया जा सके और ऐसी परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिक्री के पारित होने से व्यभिचार के आरोप का अंत हो गया है; या न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री द्वारा अध्याय को बंद कर दिया गया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने मालकिन के साथ रहना जारी रखते हुए 'गलत' किया है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बाल मणि बनाम जयंतीलाल दह्याभाई, ए. आई. आर. (1979) गुजरात के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा जताया। 209, जिसमें यह विचार लिया गया था कि व्यभिचार का वैवाहिक अपराध समाप्त हो गया है जब न्यायिक पृथक्करण की डिक्री दी गई थी, और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक नया तथ्य या गलत होने वाली परिस्थिति है जो पति के रास्ते में उस राहत को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में बाधा के रूप में खड़ी होगी जिसका वह तलाक की कार्यवाही में दावा करता है, और तर्क दिया कि इस प्रश्न का उत्तर पति के पक्ष में दिया जाना चाहिए जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। हम इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं। इस मामले में

पति की ओर से व्यभिचार में रहना एक निरंतर वैवाहिक अपराध है। अपराध केवल न्यायिक पृथक्करण के लिए एक डिक्री पारित करने पर रोक या मिटा नहीं जाता है जो जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि केवल उनके विवाह के संबंध में पति या पत्नी के कुछ कर्तव्यों और दायित्वों को निलंबित करता है और विवाह को समाप्त नहीं करता है! अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद को स्वीकार करने के मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारे विचार में, न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित करने के उद्देश्य को विफल कर देगा। गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है। दूसरी ओर, सौंदरम्मल बनाम सुंदरा महालिंगा नादर, ए. टी. आर. (1980) मद्रास-294 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में, जिसमें एक एकल फज ने यह विचार रखा कि पति जो पत्नी के कहने पर डिक्री के बाद भी व्यभिचार में रहता रहा, वह तलाक के लिए डिक्री की मांग करने वाली याचिका में सफल नहीं हो सकता है और वह खंड 23 (1) (ए) राहत को प्रतिबंधित करती है। इसमें विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया और हमारा विचार सही है कि अवैधता और अनैतिकता को किसी व्यक्ति के लिए वैवाहिक मामलों में राहत प्राप्त करने के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

पूर्वगामी पैराग्राफ में चर्चाओं और विश्लेषण पर जो स्थिति सामने आती है, वह यह है कि पहले तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया जाना है। इसलिए, उच्च न्यायालय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता को तलाक की डिक्री की राहत को अस्वीकार करने में सही था। तदनुसार अपीलों को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। सुनवाई शुल्क का आंकलन Rs.15,000 पर किया गया।

खारिज कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।